Circular No: PFRDA/2022/37/SUP-CRA/13 30th Nov 2022

CIRCULAR

To
All Govt Sector Nodal Offices, Prospective Subscribers & other NPS Stakeholders

Subject: e-NPS Govt offers ease & convenience in account opening for the Subscribers

PFRDA has enabled e-NPS for the benefit of Government Sector Subscribers & the associated Nodal offices vide our Circular no. PFRDA/2021/34/SUP-CRA/1 Dated 23rd August 2021.

2. e-NPS Govt provides the opportunity for the employees of Government Sector and empowers them to open NPS Acct with ease and lot of convenience in a paperless mode. Till date, nearly 9000 accounts are opened across various Accounting formations (refer to Annexure I) of the Central Government & State Government. The data related to accounts opened through non-e-NPS channels for the corresponding period also provided. Currently e-NPS Govt is largely used by Central Autonomous Bodies (CAB) followed by Civil & Defence Ministries.

3. The major benefits of e-NPS Govt. are faster account opening, higher efficiency and brings operational finesse to the nodal offices due to the paperless process & optimizing their time due to non-deposit of the physical account opening forms to CRA FC which are collected in other modes of acct opening. Since e NPS - Government significantly reduces the turnaround time (TAT) for Acct opening, the monthly contributions of NPS for the employees can be invested timely which lead to higher investment returns for the benefit of Subscribers.

4. It was proposed that e-NPS for Government shall be made mandatory w.e.f. 1/4/2022. However, it is observed that still various depts/nodal offices under Govt sector yet to adopt e-NPS Government holistically for the on-boarding of new employees.

5. All Govt. Nodal officers of State/Centre/Autonomous Bodies are once again informed to adopt e-NPS Government for on-boarding their new employees in order to align with the goal of Govt. of India's Digital India program to transform India into a digitally empowered society wherein its Citizens are not required for physical submission of documents & certificates. Adoption of e NPS Government also brings various benefits for stakeholders and employees as provided in Annexure II.

6. Any request for training sessions for e-NPS Government can be taken up with Protean CRA by emailing to *vijayh@proteantech.in*, *abhishekd@proteantech.in* *and* *MadhusudanD@proteantech.in*.

Chief General Manager

https://www.govtstaff.com

Annexure I

1. Government Subscribers' Accounts generated through e-NPS module

Sr. No.	Sector	Accounting Formation	As on 31 October 2022	
			Tier I	Tier II
1	Central Govt.	Civil	2,770	72
2		Postal	8	1
3		Telecom	38	2
4		Railways	591	24
5		Defence	1,927	79
6		CAB	3,304	194
7		NCT	15	1
8	State Govt.	-	110	1
9	SAB	-	1	1
		Total	**8,764**	**375**

Note
The PRANs generated through eNPS portal (Govt. sector) and currently associated with Govt. sector is shown above.

2. Government Subscribers' accounts generated through OPGM (Non-eNPS module)

Sr No	Sector	Accounting Formation	As on October 31, 2022
1	Central Govt	Civil	53,033
2		Postal	34,273
3		Telecom	54
4		Railways	48,497
5		Defence	2,795
6		CAB	5,488
7		NCT	259
8	State Govt	-	9,99,293
9	SAB	-	2,92,656
		Total	**14,36,348**

Note
1. The PRANs generated via OPGM Module (irrespective of entities generating the PRAN) and currently associated to Govt. sector were shown in the above data.
2. The PRANs (irrespective of PRAN status) generated via OPGM and not part of Govt. Sector as on October 31, 2022 are excluded.

https://www.govtstaff.com

Annexure II

Benefits of e NPS Government to Stakeholders

1. Ease of on-boarding of employees and online verification/authorization of employee NPS information by Nodal Offices.
2. Easing the work of Nodal Offices from manual process of account opening and freeing them from handling papers and associated challenges of dispatching the physical forms to CRA/ CRA FC.
3. Paperless process of enrollment with eSign/OTP.
4. Optimizing the cost of Account opening by end to end digitization.
5. Expediting the account opening process compared to existing modes of account opening methods made available to the Government Sector.
6. Timely PRAN generation and hence timely deposit of NPS contribution which would lead to higher investment benefits.
7. Since employees fill the data in eNPS portal themselves while on boarding, data entry/digitization errors may come down resulting in decline in rejection of forms.
8. Elimination of logistical cost associated with submission of physical forms by Subscribers to Nodal Offices, by Nodal Officers to CRA-FC and re-submission of forms.

https://www.govtstaff.com

परिपत्र संख्या : PFRDA/2022/37/SUP-CRA/13 30 नवम्बर 2022

परिपत्र

प्रति,

सरकारी नोडल कार्यालय, संभावित अभिदाता और अन्य एनपीएस हितधारक

विषय : ई-एनपीएस (गवर्नमेंट) अभिदाताओं के लिए खाता खोलने की सरलता और सुविधा प्रदान करता है

पीएफआरडीए ने अपने परिपत्र संख्या PFRDA/2021/34/SUP-CRA/1 दिनांकित 23 अगस्त 2021 के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं और संबद्ध नोडल कार्यालयों के लाभ के लिए ई-एनपीएस की शुरुआत की है।

2. ई एनपीएस – गवर्नमेंट, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अवसर प्रदान करता है तथा सरल और सुविधाजनक रूप से गैर-कागज़ी तरीके द्वारा एनपीएस खाता खोलना सम्भव बनाता है । अब तक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न लेखा संरचनाओं में लगभग 9000 खाते खोले गए हैं (अनुबंध I देखें)। इसी अवधि के लिए गैर-ई एनपीएस चैनल के माध्यम से खोले गए खातों से संबंधित विवरण भी प्रदान किया गया है। वर्तमान में ई-एनपीएस गवर्नमेंट का उपयोग बड़े पैमाने पर केंद्रीय स्वायत्त निकायों (CAB) द्वारा तथा उसके बाद नागरिक और रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है ।

3. ई-एनपीएस गवर्नमेंट प्रक्रिया के प्रमुख लाभ हैं - तेजी से खाता खोलना, अधिक दक्षता प्रदान करना और गैर-कागज़ी प्रक्रिया होने के कारण नोडल कार्यालयों के लिए परिचालन कुशलता लाना तथा खाता खोलने के अन्य तरीकों में एकत्र किए जाने वाले भौतिक फ़ार्म को सीआरए एफसी के पास जमा न करने के कारण उनके समय को अनुकूलित करना। चूंकि ई एनपीएस – गवर्नमेंट, खाता खोलने के लिए टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) की समयसीमा को काफी कम कर देती है, इसलिए कर्मचारियों के लिए एनपीएस के मासिक अंशदान का समय पर निवेश किया जा सकता है जिससे अभिदाताओं के लाभ के लिए उच्च निवेश रिटर्न मिल सकता है।

4. ई-एनपीएस (गवर्नमेन्ट) को दिनांक 1/4/2022 से अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, यह देखा गया है कि अभी भी सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विभागों/नोडल कार्यालयों द्वारा नए कर्मचारियों के ऑन-बोर्डिंग के लिए ई-एनपीएस गवर्नमेंट को समग्र रूप से अपनाया जाना बाकी है।

5. राज्य / केंद्र / स्वायत्त निकायों के सभी सरकारी नोडल अधिकारियों को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे अपने नए कर्मचारियों की ऑन-बोर्डिंग के लिए ई-एनपीएस गवर्नमेंट प्रक्रिया को अपनाएं ताकि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने के लक्ष्य को संरेखित किया जा सके, जिसमें नागरिकों को दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हो। ई एनपीएस गवर्नमेंट को अपनाने से हितधारकों और कर्मचारियों को अनेक लाभ भी मिलते हैं, जो अनुलग्नक II में दिए गए हैं ।

बी - १४/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय ,नई दिल्ली - ११० ०१६
दूरभाष: 011 - 26517501, 26133730, 26133730 फैक्स: 011 – 26517507, वेबसाइट: www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110 016
Phone : 011 - 26517501, 26133730, 26133730 Fax: 011 – 26517507 website: www.pfrda.org.in

https://www.govtstaff.com

6. ई-एनपीएस गवर्नमेंट पर प्रशिक्षण सत्र के लिए किसी भी प्रकार के अनुरोध हेतु प्रोटियन सीआरए को vijayh@proteantech.in, abhishekd@proteantech.in और MadhusudanD@proteantech.in पर ईमेल किया जा सकता है।

मुख्य महाप्रबंधक

https://www.govtstaff.com

अनुलग्नक I

1. ईएनपीएस मॉड्यूल के माध्यम से जनित सरकारी अभिदाताओं के खाते

क्र.सं.	क्षेत्र	लेखा संरचना	31 अक्तूबर 2022	
			टियर I	टियर II
1.	केंद्र सरकार	नागरिक	2,770	72
2.		डाक	8	1
3.		टेलीकाम	38	2
4.		रेलवे	591	24
5.		रक्षा	1,927	79
6.		केन्द्र स्वायत्त निकाय	3,304	194
7.		एनसीटी	15	1
8.	राज्य सरकार	-	110	1
9.	राज्य स्वायत्त निकाय	-	1	1
		कुल	**8,764**	**375**

टिप्पणी

ई एनपीएस पोर्टल (सरकारी क्षेत्र) के माध्यम से जनित और वर्तमान में सरकारी क्षेत्र से सम्बंधित प्रान ऊपर वर्णित है।

2. ओपीजीएम (गैर-ईएनपीएस मॉड्यूल) के माध्यम से जनित सरकारी अभिदाताओं के खाते

क्र.सं.	क्षेत्र	लेखा संरचना	31 अक्तूबर 2022 तक के अनुसार
1.	केंद्र सरकार	नागरिक	53,033
2.		डाक	34,273
3.		टेलीकाम	54
4.		रेलवे	48,497
5.		रक्षा	2,795
6.		केन्द्र स्वायत्त निकाय	5,488
7.		एनसीटी	259
8.	राज्य सरकार	-	9,99,293
9.	राज्य स्वायत्त निकाय	-	2,92,656
		कुल	**14,36,348**

टिप्पणी

1. *ओपीजीएम् मोड्यूल (प्रान जनित करने वाली इकाईयों का सन्दर्भ लिए बिना) के माध्यम से जनित और वर्तमान में सरकारी क्षेत्र से सम्बंधित प्रान ऊपर के आंकड़ों में वर्णित है।*
2. *दिनांक 31 अक्तूबर 2022 तक के अनुसार, ओपीजीएम् के माध्यम से जनित और सरकारी क्षेत्र से अलग प्रान (प्रान स्थिति का सन्दर्भ लिए बिना) को छोड़ दिया गया है।*

https://www.govtstaff.com

अनुलग्नक ॥

<u>हितधारकों के लिए ई एनपीएस गवर्नमेंट प्रक्रिया के लाभ</u>

1. नोडल कार्यालयों द्वारा कर्मचारियों की ऑन-बोर्डिंग में सरलता और कर्मचारी से सम्बंधित एनपीएस जानकारी का ऑनलाइन सत्यापन / प्रमाणीकरण ।

2. नोडल कार्यालयों द्वारा खाता खोलने सम्बन्धी मैनुअल प्रक्रिया को सरल बनाना और उन्हें प्रपत्रों को प्रबंधित करने और सीआरए/सीआरए एफसी को भौतिक फॉर्म भेजने से जुड़ी चुनौतियों से मुक्त करना।

3. ई-साइन/ओटीपी के साथ नामांकन की गैर-कागज़ी प्रक्रिया।

4. एन्ड टू एन्ड डिजिटलीकरण द्वारा खाता खोलने की लागत का अनुकूलन।

5. सरकारी क्षेत्र को उपलब्ध कराए गए खाता खोलने के मौजूदा तरीकों की तुलना में खाता खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाना।

6. समय पर प्रान जनित करना और परिणामस्वरुप एनपीएस अंशदान को समय पर जमा करना जिससे उच्च निवेश लाभ हो।

7. ऑनबोर्डिंग के दौरान ईएनपीएस पोर्टल में कर्मचारियों द्वारा स्वयं डेटा भरे जाने के कारण डेटा एंट्री / डिजिटलीकरण त्रुटियों में कमी आ सकती है जिसके परिणामस्वरूप फॉर्म अस्वीकरण में गिरावट की संभावना।

8. अभिदाताओं द्वारा नोडल कार्यालयों को तथा नोडल अधिकारियों द्वारा सीआरए-एफसी को भौतिक प्रपत्र जमा करने से सम्बन्धित और उन्ही प्रपत्रों को बार-बार जमा करने से संबंधित लॉजिस्टिक कॉस्ट को समाप्त करना।

https://www.govtstaff.com